

एग्री क्रेडिट के लिए नए सिरे से शुरुआत करने की आवश्यकता

सामान्य अध्ययन – पेपर 3: किसानों की सहायता में ई-तकनीक; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे ।

कीवर्ड : क्रेडिट में विषम क्षेत्रीय वितरण, फसल सघनता, ऑयल पाम मिशन, एक जिला एक उत्पाद, मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण, एफपीओ आधारित वित्तपोषण ।

चर्चा में क्यों -

- विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में कृषि ऋण में सराहनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, कृषि के लिए एक बेहतर क्षेत्रीय वितरण क्रेडिट आवश्यक है।



कृषि में निवेश की स्थिति :

- 2000-2001 में कृषि में निवेश दर (कृषि में सकल पूंजी निर्माण का कृषि-जीडीपी से अनुपात) 12 प्रतिशत थी जो 2011-12 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान में 2020-21 में बढ़कर 15.9 प्रतिशत हो गयी है।
- निजी क्षेत्र का निवेश कृषि में पूंजी निर्माण का लगभग 80 प्रतिशत है और बैंक ऋण प्रमुख चालक है।
- दक्षिण (जो सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) का 18 प्रतिशत है) देश में वितरित कुल कृषि ऋण में लगभग 45 प्रतिशत की भागीदारी करता है।

- दूसरी ओर, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जो सकल फसली क्षेत्र का 43 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, उनकी कृषि ऋण में केवल 22 प्रतिशत की भागीदारी है।
- फसल सघनता, ऋण की संभावित मांग का संकेत, अब पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में अधिक है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 0.2 प्रतिशत (2000-2001) से बढ़कर वर्तमान में लगभग 0.75 प्रतिशत हो गई है।
- इस क्षेत्र में बागवानी के विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह सुदूर पूर्व के साथ हमारी संबद्धता को बढ़ाने के लिए दरवाजे खोलता है।

क्रेडिट में विषम क्षेत्रीय वितरण के लिए जिम्मेदार कारक :

- बेहतर बुनियादी ढाँचा और कानून व्यवस्था, बैंकों के बीच अधिक मात्रा में उधार देने के लिए विश्वास बढ़ाती है।
- शाखाओं का स्थान तय करते समय, बैंक सिंचाई की उपलब्धता और विश्वसनीय वर्षा पैटर्न वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं जो बाढ़ और सूखे की आशंकाओं को दूर करते हैं।
- स्वाभाविक रूप से, ऐसे स्थान कम जोखिम वाली कृषि और उच्च भुगतान दरों का समर्थन करते हैं।

खाद्य तेल और कृषि ऋण का संबंध :

- फिलहाल भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 50 फीसदी खाद्य तेल का आयात करता है।
- आयातित खाद्य तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने हाल ही में **ऑयल पाम मिशन** जैसी पहल की है, जिसमें तिलहन फसलों की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- इससे किसानों को भी लाभ होता है क्योंकि ताड़ के तेल (पाम ऑयल) के उत्पादन के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि लाने से कृषि और प्रसंस्करण के लिए ऋण की मांग में वृद्धि होगी।

खाद्य तेल-पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ -ओपी) :

- एनएमईओ -ओपी, 2021 में स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर पाम ऑयल (ताड़ के तेल) का उत्पादन करना है।
- इसका उद्देश्य 2025-26 तक पाम ऑयल (ताड़ के तेल) की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर करना है।
- पाम ऑयल उत्पादक किसानों को मूल्य और व्यवहार्यता सूत्र के तहत आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
- योजना का एक अन्य फोकस क्षेत्र इनपुट्स/हस्तक्षेपों के समर्थन को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है।
- पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए नए सिरे से पौधरोपण करने के लिए विशेष रूप से सहायता दी जा रही है।

- क्षेत्रों में अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण योजना का विशेष जोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर होगा।

मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण के लिए उत्पादन प्रणालियों और कृषि ऋण का संबंध :

- ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद योजना - वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) जैसी पहल उत्पादन प्रणालियों को बाजारों से जोड़ेगी, साथ ही मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण को सुदृढ़ करेगी।
- वर्तमान कृषि ऋण वितरण काफी हद तक व्यक्तिगत आधारित है, और मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण कुशल नकदी प्रवाह का मार्ग प्रशस्त करेगा जहां जोखिम को कमोडिटी मूल्य श्रृंखला में साझा किया जाता है।

कृषि ऋण का डिजिटलीकरण :

- यदि उत्पादन और विपणन प्रणाली दोनों को जोड़ा जा सकता है तो कृषि ऋण के डिजिटलीकरण में मूल्य निर्माण और ऋण के विस्तार के लिए अपार संभावनायें हैं।
- **ई-नाम** जैसे कृषि विपणन मोर्चे पर डिजिटलीकरण के प्रयासों का उद्देश्य वस्तुओं में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। इस तरह के नवाचार से न केवल ऋण का विस्तार होगा बल्कि दक्षता में भी सुधार होगा।

एफपीओ-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से अंतराल को पाटना :

- वर्तमान में, कृषि ऋण परिदृश्य उत्पादन पक्ष की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है, और विपणन और कटाई के बाद की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत ऋण-कवर से वंचित हैं (उत्पाद परिदृश्य सहित)।
- एफपीओ आधारित डिजिटलीकरण इस अंतर को तेजी से पाट सकता है।
- एफपीओ, बैंकों और एनबीएफसी के साथ मूल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण चालक हो सकते हैं जो श्रृंखला का वित्तपोषण करते हैं।
- एफपीओ वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड सपोर्ट एक समय वाल्व है जो एफपीओ के लिए क्रेडिट प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है।

फिनटेक-आधारित क्रेडिट वितरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन परिदृश्य बदलना :

- स्टार्ट-अप तेजी से और कुशलता से डिजिटल साधनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में डिजिटल उत्पादों को लक्षित और वितरित कर रहे हैं।
- यूपीआई की सफलता और इसे ग्रामीण या शहरी सभी क्षेत्रों में तेजी से अपनाने से प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के बारे में संदेह समाप्त हो गया है।
 - एनबीएफसी अंतिम किसान तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं क्योंकि वे पारंपरिक ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं की तुलना में प्रौद्योगिकी का गहनता से उपयोग कर रहे हैं।

- 2016 से 2020 की अवधि के लिए एनबीएफसी का सकल अग्रिम 15.7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा। इसी अवधि के दौरान, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के अग्रिमों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- एनबीएफसी क्षेत्र के कुल सकल अग्रिमों में कृषि और संबंधित गतिविधियों की हिस्सेदारी में 2.38 प्रतिशत (2017 और 2018) और 3.06 प्रतिशत (2019) के बीच उतार-चढ़ाव आया है।
- डिजिटल ऋण पहले से ही वित्तीय समावेशन परिदृश्य को बदल रहा है।
- इस प्रकार, फिनटेक-आधारित क्रेडिट समावेशन में बड़ी क्षमता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे प्रभावी उत्प्रेरक साबित हो सकता है।

निष्कर्ष:

- संस्थानों द्वारा कृषि ऋण प्रणाली में नवोन्मेष संभावित होने के बावजूद अव्यवस्थित हैं।
- अल्पकालिक ऋण संवितरण के लिए ब्याज दर में छूट जैसे उपाय नवाचार को रोकते हैं।
 - एक वैकल्पिक चैनल जैसे रीकॉन्फ़िगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किसानों को सब्सिडी दे सकता है, जबकि पुनर्गठन/राइट-ऑफ एक तदर्थ विकल्प होना चाहिए।
- डिजिटल डीबीटी, भुगतान के लिए यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे प्रयासों ने निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाया है।
- यह इन हस्तक्षेपों का लाभ उठाने और डिजिटल उत्पादों का एक जाल बिछाने का समय है ताकि प्रौद्योगिकी पर सवार होकर कृषि ऋण प्रणाली में प्रवेश किया जा सके ताकि यह विस्तार और ऋण वितरण की दक्षता दोनों के मामले में एक बेहतर प्रणाली की ओर बढ़ सके।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. निजी क्षेत्र का निवेश कृषि में पूंजी निर्माण का लगभग 80 प्रतिशत है।
2. दक्षिणी क्षेत्र देश में वितरित कुल कृषि ऋण का लगभग 45 प्रतिशत लेता है।
3. पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में फसल सघनता अधिक होती है।
4. भारत में कृषि ऋण परिदृश्य कृषि की कटाई के बाद की आवश्यकताओं की ओर अत्यधिक झुका हुआ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3

(d) ऊपर के सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या :

- निजी क्षेत्र का निवेश कृषि में पूंजी निर्माण का लगभग 80 प्रतिशत है और बैंक ऋण प्रमुख चालक है। इस प्रकार, कथन कथन 1 सत्य है।
- दक्षिण (जो सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) का 18 प्रतिशत हिस्सा रखते है) देश में वितरित कुल कृषि ऋण का लगभग 45 प्रतिशत रखते है। इस प्रकार, कथन 2 सत्य है।
- दूसरी ओर, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र सकल फसली क्षेत्र का 43 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, लेकिन कृषि ऋण में उनकी भागीदारी केवल 22 प्रतिशत है।
- फसल सघनता, ऋण की संभावित मांग का संकेत, अब पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में अधिक है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 0.2 प्रतिशत (2000-2001) से बढ़ी है और वर्तमान में लगभग 0.75 प्रतिशत है। इस प्रकार, कथन 3 सत्य है।
- वर्तमान में, कृषि ऋण परिदृश्य उत्पादन पक्ष की ओर अत्यधिक झुका हुआ है, विपणन और कटाई के बाद की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत ऋण-अभाव का शिकार हैं (उत्पाद परिदृश्य सहित)। अतः कथन 4 असत्य है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्र. विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में कृषि ऋण में सराहनीय दर से वृद्धि हुई है। हालाँकि, कृषि ऋण का बेहतर क्षेत्रीय वितरण आवश्यक है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

स्रोत: द हिंदू बीएल